सुभाष चंद

बनाम

राज्य (दिल्ली प्रशासन)

(2013 की आपराधिक अपील 50)

8 जनवरी, 2013

[आफताब आलम और रंजना प्रकाश देसाई, जेजे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 378 (2005 के अधिनियम 25 द्वारा संशोधित)-राज्य/राज्य द्वारा दायर शिकायत मामलाप्राधिकरण-मजिस्ट्रेट को बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील -केवल उच्च न्यायालय को किसी भी प्रकार के दोषमुक्त करने का आदेश दंडनीय अपराधों का आरोप लगाने वाली शिकायत का तत्काल मामला धारा 16 (1) (1ए) आर/डब्ल्यू एस। 7 पी.एफ.ए. अधिनियम और पी.एफ.ए. नियम दायर किए गए थेअपीलार्थी शिकायतकर्ता के खिलाफ स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण दिल्ली प्रशासन के माध्यम से लेकिन अपीलार्थी को बरी कर दिया गयामेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा-शिकायतकर्ता कर सकता है के लिए एक आवेदन दायर करके बरी होने के आदेश को चुनौती दें उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए विशेष अनुमति, न कि सत्र न्यायालय-इसलिए, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि मामला एस द्वारा शासित नहीं था। 378 (4) सी.आर.पी.सी. रद्द और

सेट किया गया एक तरफ-खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 1954 एस. 16 (1) (1ए) आर/डब्ल्यू एस। 7-खाद्य मिलावट रोकथाम नियम।

उच्च न्यायालय, विवादित निर्णय द्वारा,अपीलार्थी द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी गई जिसमें कहा गया था कि बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ राज्य द्वारा दायर अपीलदंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 (1) के तहत सत्र न्यायालय में झूठ बोलना औरउच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 (4) के तहत नहीं।

जिस प्रश्न पर विचार किया जाना था तत्काल अपील यह थी कि क्या किसी शिकायत मामले में, एक 192 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को बरी करने के आदेश के खिलाफ अपीलधारा 378 (1) (ए) सी. आर. पी. सी. के तहत सत्र न्यायालय में झूठ बोलना या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 (4) के तहत उच्च न्यायालय में।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :-

1.1. विवाद को समझने के लिए, यह हैसी. आर. पी. सी. की धारा 378 पर विचार करना आवश्यक है।2005 के अधिनियम 25 और धारा 378 द्वारा संशोधन जिससे। [पैरा 10] [202-सी]

1.2. पूर्व में असंशोधित धारा 378 (1) सी.आर.पी.सी. के तहत, राज्य सरकार, किसी भी मामले में, निर्देश दे सकती है लोक अभियोजक उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करेगा द्वारा पारित दोषमुक्ति के मूल या अपीलीय आदेश से सत्र न्यायालय द्वारा संशोधन में पारित किया गया।

धारा 378 (2) में ऐसे मामले शामिल हैं जिनमें बरी करने का आदेश पारित किया गया था। कोई भी मामला जिसमें अपराध की जाँच की गई थी दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के तहत गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 या किसी अन्य द्वाराजांच करने के लिए सशक्त अन्य एजेंसी संहिता के अलावा किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के तहत अपराध। में। ऐसे मामलों में, केंद्र सरकार भी निर्देश दे सकती है लोकअभियोजक उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करेगा बरी करने के आदेश से। धारा 378 (3) में कहा गया है कि धारा 378 की उप-धारा (1) और (2) के तहत अपील कोड पर छुट्टी के अलावा विचार नहीं किया जा सका उच्च न्यायालय से। संहिता की धारा 378 की उप-धारा (4) में किसी भी मामले में बरी करने के आदेश दिए गए हैं। शिकायत पर स्थापित। इस प्रावधान के अनुसार, यदि शिकायतकर्ता द्वारा किए गए एक आवेदन पर, उच्च न्यायालय ने न्यायालय ने आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान की बरी होने पर, शिकायतकर्ता ऐसी अपील प्रस्तुत कर सकता है उच्च न्यायालय तक। धारा 378 की उप-धारा (5) कोड सीमा की अवधि के लिए प्रदान किया गया है। संहिता की धारा 378 की उप-धारा (6) में कहा गया है कि यदि किसी भी मामले में, विशेष 193 के अनुदान के लिए उप-धारा (4) के तहत आवेदन।

सुभाष चंद बनाम राज्य (दिल्ली) प्रशासन बरी करने के आदेश से अपील करने की अनुमति से इनकार कर दिया जाता है, नहीं बरी करने के उस आदेश से अपील उप के तहत होगी।

धारा (1) या (2)। इस प्रकार, यदि उच्च न्यायालय ने अनुदान देने से इनकार कर दियाशिकायतकर्ता को अपील करने के लिए विशेष अनुमति, शिकायतकर्ता से कोई अपील नहीं बरी करने का आदेश राज्य या धारा 378 (2) में अनुध्यात अभिकरण द्वारा दायर किया जा सकता है। यह स्पष्ट है किये प्रावधान जो पहले किसी आदेश के खिलाफ अपील करते थे बरी होने का फैसला केवल उच्च न्यायालय के पास ही हो सकता है। उप-खंड (4) इसका उद्देश्य बरी करने के आदेशों को अंतिम रूप देना था। [पैरा 11], [203-जी-एच; 204-ए-एफ]

1.3 अधिनियम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 में संशोधन के बाद 25 2005 की धारा 378 (1) (ए) और (बी) के विश्लेषण पर, यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार जनता को निर्देश नहीं दे सकती हैअभियोजक बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगाएक संज्ञेय के संबंध में एक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित और श्रेणी बद्ध प्रतिबंध के कारण गैर-जमानती अपराध अपराध केवल सत्र न्यायालय में दायर किया जा सकता है द्वारा निर्देशित लोक अभियोजक का उदाहरण जिला मजिस्ट्रेट। धारा 378 (1) (बी) में इन शब्दों का उपयोग किया गया है। इसलिए, अन्य सभी मामलों में जहां बरी करने के आदेश पारित किए जाते हैं, लोक अभियोजक द्वारा

अपील दायर की जा सकती है राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय को निर्देश दिया गया। [पैरा 16] [208 जी-एच; 209-ए-सी]

1.4 उप-धारा 378 की धारा (4) में प्रावधान किया गया है शिकायत पर स्थापित मामले में बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील के लिए। इसमे कहा गया है कि यदि शिकायतकर्ता उच्च न्यायालय में आवेदन करता है औरउच्च न्यायालय अपील करने के लिए विशेष अनुमति देता है, शिकायतकर्ता उच्च 194 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2013] 1 एस. सी. आर. को ऐसी अपील प्रस्तुत कर सकता है।अदालत। यह उप-खंड 'विशेष अवकाश' की बात करता है अन्य अपीलों से संबंधित उप-धारा (3) के विरुद्ध जो 'छुट्टी' की बात करते हैं। इस प्रकार, एक के खिलाफ शिकायतकर्ता की अपील बरी करने का आदेश अपने आप में एक श्रेणी है। शिकायतकर्तावह कोई निजी व्यक्ति या लोक सेवक हो सकता है। यह है। उप-धारा (5) से स्पष्ट है जो अनुप्रयोग को संदर्भित करता है शिकायतकर्ता द्वारा 'विशेष अवकाश' के लिए दायर किया गया। यह छह अनुदान देता है। एक शिकायतकर्ता के लिए महीनों की सीमा की अवधि जो एक लोक सेवक और प्रत्येक अन्य मामले में दाखिल करने के लिए साठ दिन आवेदन। उप-धारा (6) महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि यदि किसी भी मामले में शिकायतकर्ता का 'विशेष अवकाश' के लिए आवेदन

दोषमुक्ति उप-धारा (1) या उप-धारा (1) के तहत होगी। खंड (2)। इस प्रकार, यदि शिकायतकर्ता को बरी करने के आदेश के

खिलाफ अपील करने के लिए 'विशेष अनुमति' नहीं दी जाती है, तो बात वहीं खत्म होनी चाहिए। न ही जिला मजिस्ट्रेट ने राज्य सरकार उस आदेश के खिलाफ अपील कर सकती है दोषमुक्त। विचार को शांत करने के लिए प्रतीत होता है ऐसी स्थिति में। [पैरा 17] [209-सी-जी]

1.5 पुलिस रिपोर्ट को धारा 2 (आर) के तहत परिभाषित किया गया है। संहिता का अर्थ एक पुलिस अधिकारी द्वारा अग्रेषित एक रिपोर्ट है धारा 173 की उप-धारा (2) के तहत मजिस्ट्रेट को कोड। यह पुलिस द्वारा की गई जाँच की परिणति है संज्ञेय की जानकारी प्राप्त करने के बाद एक अपराध या एक संज्ञेय अपराध। धारा 2 (डी) ए को परिभाषित करती है मौखिक रूप से या मौखिक रूप से लगाए गए किसी भी आरोप का अर्थ है शिकायतमजिस्ट्रेट को उसकी कार्रवाई करने की दृष्टि से लिखना संहिता के तहत, कि कोई व्यक्ति, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात ने अपराध किया है, लेकिन नहीं करता है एक पुलिस रिपोर्ट शामिल करें। धारा 2 (डी) के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि एक मामले में एक पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट जो जांच के बाद खुलासा करता है, एक गैर के आयोग संज्ञेय अपराध को शिकायत माना जाएगा, और वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की जाती है, शिकायतकर्ता माना जाए। कभी-कभी सुभाष चंद बनाम के तहत किए गए संज्ञेय अपराध की जांच।संहिता की धारा 154 शिकायत में परिणत हो सकती है।मामला (औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत मामले)। एफ.ए. (खाद्य मिलावट रोकथाम

अधिनियम) के तहत, 1954) इससे पहले शिकायत दर्ज करने पर मामले दर्ज किए जाते हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का न्यायालय जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है पी.एफ.ए. अधिनियम की धारा 20 और पी.एफ.ए. अधिनियम के तहत अपराध दोनों संज्ञानात्मक और गैर-संज्ञानात्मक हैं। इस प्रकार, क्या एक मामला एक शिकायत पर स्थापित एक मामला है जो उसमें शामिल अपराध से संबंधित कानूनी प्रावधानों पर निर्भर करता है। लेकिन एक बार जब यह एक शिकायत पर मामला दर्ज किया जाता है और दोषमुक्ति का आदेश पारित किया जाता है, चाहे अपराध जमानती या गैर-जमानती, संज्ञेय या गैर-संज्ञेय,शिकायतकर्ता धारा के तहत आवेदन दायर कर सकता है। 378 (4) उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए अदालत। धारा 378 (4) पर कोई प्रतिबंध नहीं है शिकायतकर्ता। जहाँ तक राज्य का संबंध है, तदनुसार मूल या मूल से उच्च न्यायालय में अपील दायर करें। किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित बरी करने का अपीलीय आदेश उच्च न्यायालय की तुलना में। लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर्निहित है और राज्य की शक्ति पर स्पष्ट प्रतिबंध। यह नहीं हो सकता। लोक अभियोजक को एक से अपील प्रस्तुत करने का निर्देश देंएक के संबंध में एक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित बरी करने का आदेश संज्ञेय और गैर-संज्ञेय अपराध। ऐसे में जिला मजिस्ट्रेट धारा 378 (1) (ए) के तहत निर्देश दे सकता है। लोक अभियोजक सत्र में अपील दायर करने के लिए अदालत। यह संहिता की धारा 378 का सही दृष्टिकोण और सही व्याख्या प्रतीत होती है। [पैरा 18] [209-एच; 210-ए-एच; 211]

1.6 2005 के अधिनियम No.25 ने एक प्रमुख संहिता में संशोधन। इसने धारा 378 (1) (ए) पेश की जिसने जिला मजिस्ट्रेट को किसी भी मामले में अनुमति दी - लोक अभियोजक को संज्ञेय और गैर-जमानती 196 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्टों के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दें। अपराध। पहली बार एक प्रावधान पेश किया गया थाजिसके तहत बरी करने के आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है। इस तरह की अपीलें थीं और गैर-जमानती अपराध। धारा 378 (1) (बी) विशेष रूप से और स्पष्ट शब्दों में राज्य के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया ऐसी अपीलें दायर करना। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार, किसी भी मामले में, लोक अभियोजक को प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है मूल या अपीलीय से उच्च न्यायालय में अपील उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित बरी करने का आदेश न्यायालय खंड (क) या आदेश के तहत आदेश नहीं है सत्र न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में बरी किया जाना। इस प्रकार, राज्य सरकार इसके खिलाफ अपील प्रस्तुत नहीं कर सकती है। इस संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित बरी करने का आदेश संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध। का खंड 37 भारत के विधि आयोग की 154 वीं रिपोर्ट और दंड प्रक्रिया संहिता का खंड 37(संशोधन) विधेयक, 1994 में कहा गया है कि सुरक्षा के लिए शक्ति के मनमाने प्रयोग के खिलाफ और कम करने के लिएलापरवाही से बरी करने के लिए धारा 378 की मांग की गई थी बरी करने के आदेश के खिलाफ

अपील करने के लिए संशोधन किया गया संज्ञेय और गैर के संबंध में एक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित जमानतीय अपराध। इस प्रकार यह कदम उठाया गया विधायिका मनमाने ढंग से और लापरवाही से बरी होने की जाँच करे। ऐसा प्रतीत होता है कि अपरिवर्तित में वृद्धि के प्रति सचेत होनाजिला मजिस्ट्रेट को जनता को निर्देश देने में सक्षम बनायाअभियोजक सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के लिए, जिससे थकाऊ और समय लेने से बचा जा सके। प्रस्ताव के साथ राज्य से संपर्क करने की प्रक्रिया, इसे मंजूरी दिलवाना और फिर अपील दायर करना। [पैरा 19] [211-सी-एच; 212-ए-बी]

1.7 2005 के अधिनियम 25 द्वारा धारा 378 में संशोधन किया गया था।लेकिन अधिनियम 25 द्वारा धारा 378 में किया गया प्रमुख संशोधन 2005 को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसका एक उद्देश्य है। ऐसा नहीं है 1 समुदाय की सुरक्षा की चिंता को ध्यान में रखें हवाएँ चल रही हैं। वास्तव में, यह कुछ लोगों के खिलाफ अपील दायर करता है। धारा 378 (1) (ए) में वर्णित दोषमुक्ति आदेशों के प्रकार आसान, कम बोझिल और कम समय लेने वाला। [पैरा20] [212 सी-डी]

1.8 एक शिकायतकर्ता, इस प्रकार, एक आवेदन दायर कर सकता हैकिसी को भी बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमतिकेवल उच्च न्यायालय को कृपया। वह सत्र न्यायालय में ऐसी अपील दायर नहीं कर सकता है। तत्काल मामले में शिकायत धारा 16 (1)

(1ए) के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाना। भोजन की रोकथाम की धारा 7 के साथ पढ़ें मिलावट अधिनियम, 1954 और खाद्य निवारणमिलावट नियम, 1955 शिकायतकर्ता स्थानीय द्वारा दायर किया गया था।दिल्ली प्रशासन के माध्यम से स्वास्थ्य प्राधिकरण। उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए आवेदन दायर करना न्यायालय में और सत्र न्यायालय में नहीं। इसलिए, विवादित आदेश जिसमें कहा गया है कि यह मामला शासित नहीं है धारा 378 (4) सी. आर. पी. सी. द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। [पैरा 21] [212 ई-एच]

खेमराज बनाम. मध्य प्रदेश राज्य 1976 (1) एससीसी 385: 1976 (2) एस.सी.आर. 753; राज्य (दिल्ली प्रशासन) v. धर्मपाल 2001 (10) एससीसी 372: 2001 (4) पूरक। एस.सी.आर. 448; अकालू अहिर और अन्य बनाम रामदेव राम 1973 (2) एससीसी 583: 1974 (1) एस.सी.आर. 130; राज्य बनाम राम बाबू और अन्य। 1970 ए.डब्ल्यू.आर. 288; खाद्य निरीक्षक बनाम मोइडू 1988 (2) के.एल.टी. 205; प्रसन्नाचारी बनाम चिक्कापिनाचारी और अन्य। 1959 ए.आई.आर. (कांत) 106; राज् महाराष्ट्र बनाम लिम्बाजी सयाजी म्हास्के, ग्राम पंचपंचायत 1976 (माह.) एल.जे. 475; पंजाब और अन्य राज्य बनाम जगन नाथ 1986 (90) पी.एल.आर. 466 और उड़ीसा राज्य बनाम स्वप्नेश्वर थप्पा 1987 सीआरएल.जे. 612 लागू नहीं किया गया।

भारतीय विधि आयोग की 154 वीं रिपोर्ट और 221 वीं रिपोर्ट संदर्भित किया गया।

केस कानून संदर्भित

1976 (2) एससीआर 753	अनुपयुक्त ठहराया गया	पैरा 9
2001(4)पूरक एस.सी.आर 448	अनुपयुक्त ठहराया गया	पैरा 9
1974 (1) एससीआर 130	अनुपयुक्त ठहराया गया	पैरा 9
1970 ए.डब्ल्यू.आर 288	अनुपयुक्त ठहराया गया	पैरा 9
1988 (2) के.एल.टी 205	अनुपयुक्त ठहराया गया	पैरा 9
1959 एआईआर (कांत) 106	अनुपयुक्त ठहराया गया	पैरा 9
1976 (माह.) एलजे 475	अनुपयुक्त ठहराया गया	पैरा 9
1986 (90) पीएलआर 466	अनुपयुक्त ठहराया गया	पैरा 9
1987 सीआरएल.जे. 612	अनुपयुक्त ठहराया गया	पैरा 9

आपराधिक अपील न्यायिकक्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 50/2013

उच्च न्यायालय नई दिल्ली में दिल्ली की अदालत के आपराधिक विविध मामले में 2009 का सं. 427 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 07.01.2011 से।

सिद्धार्थ लूथरा (न्याय मित्र), पी.पी. मल्होत्रा, एएसजी, देवीना सहगल, मीनाक्षी लेखी, हरीश पांडे, सचिन जैन, यासिर रउफ, रंजना नारायण (अनिल कटियार के लिए) पार्टियाँ।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था।

(एसएमटी.) रंजना प्रकाश देसाई, जे. 1. छोड़ दें, दिया गया।

2. यह अपील, विशेष अनुमति द्वारा, इसके खिलाफ निर्देशित है। आपराधिक विविध मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित 07/01/2011 दिनांकित निर्णय और आदेश। 2009 का मामला संख्या 427 जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। यह अभिनिर्धारित करते हुए कि राज्य द्वारा एक आदेश के विरुद्ध दायर की गई अपील धारा 378 (1) के तहत सत्र न्यायालय को बरी किया जाएगा। [रंजन प्रकाश देसाई, जे.] दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, "संहिता") और उच्च न्यायालय को संहिता की धारा 378 (4) के तहत नहीं।

3. अपीलार्थी इसका आपूर्तिकर्ता-सह-निर्माता होता है खाद्य पदार्थ जिनका नाम मीठा कार्बोनेटेड पानी है। वह है मैसर्स के नाम और शैली में व्यवसाय करना। सुभाष सोडा जल कारखाना। 6/6/1989 पर शाम लगभग 4.15 बजे, एक पी. एन. खाद्य निरीक्षक खत्री ने मीठे का एक नमूना खरीदा एक दया चंद जैन से विश्लेषण के लिए कार्बोनेटेड पानी, सूरज सिनेमा, धनसा में कैंटीन के विक्रेता-सह-ठेकेदार, नजफगढ़, दिल्ली। आवश्यक

प्रक्रिया का पालन करने के बाद, नमूना विश्लेषण के लिए सार्वजनिक विश्लेषक के पास भेजा गया था। उस पर निर्धारित मानक के अनुरूप। समापन के बाद जाँच, प्रत्यर्थी-अपने स्थानीय स्वास्थ्य के माध्यम से राज्य प्राधिकरण-पी. के. जयस्वाल ने संख्या 64 वाली शिकायत दर्ज कराई 1991 न्यायालय में अपीलार्थी और दया चंद के विरुद्ध मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली ने आरोप लगाया कि अपीलार्थी और उक्त दया चंद ने प्रावधानों का उल्लंघन किया था धारा 2 (आई.ए.), (ए.), (बी.), (एफ.), (एच.), (आई.), (एम.), धारा 2 (आई.एक्स.) (जे.), (के) और खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 24 (संक्षेप में, "पी.एफ.ए. अधिनियम") और नियम 32, नियम 42 (जेडजेडजेड) (आई) और खाद्य मिलावट रोकथाम नियम, 1955 का नियम 47 (संक्षेप में, "नियम'') और इसके तहत दंडनीय अपराध किया। पी.एफ.ए. अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 16 (1) (1ए) और नियम। चूंकि दया चंद की मृत्यु विचाराधीनता के दौरान हुई थीमामला, उसके खिलाफ मामला समाप्त हो गया। अपीलार्थी पर मुकदमा चलाया गया और विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 27/2/2007 के आदेश द्वारा बरी कर दिया गया।

4. 27/2/2007 दिनांकित उक्त आदेश से व्यथित होने के कारण, प्रतिवादी-राज्य ने 2008 में आपराधिक अपील संख्या 13 को प्राथमिकता दीसंहिता की धारा 378 (1) (ए) के तहत सत्र न्यायालय। अपीलार्थी ने सत्र न्यायालय के समक्ष उक्त अपील की स्थिरता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति

उठाई संहिता की धारा 378 (4) को देखते हुए। उन्होंने तर्क दिया कि एक शिकायत मामले में बरी होने के आदेश से उत्पन्न अपील उच्च न्यायालय से झूठ बोलेगा। उक्त आपत्ति को खारिज कर दिया गया था सत्र न्यायालय दिनांक 4/2/2009 के आदेश द्वारा।

5. दिनांकित 4/2/2009 के उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने क्रिमिनल मिस्क को प्राथमिकता दी। 2009 से पहले का मामला संख्या 427 उच्च न्यायालय। दिनांकित 9/7/2009 आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सत्र न्यायालय को इस पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है एक शिकायत मामले में दायर की गई अपील और निर्देश दिया कि अपील इसे स्थानांतरित करें। तदनुसार, 2008 की आपराधिक अपील संख्या 13 सत्र न्यायालय के समक्ष लंबित मामले को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया न्यायालय और 2009 की आपराधिक अपील No.642 के रूप में पुनः क्रमांकित।

6. प्रत्यर्थी-राज्य ने 9/7/दिनांकित उक्त आदेश का पालन किया। 2009 विशेष अनुमति याचिका (सी. आर. एल.) द्वारा इस न्यायालय को No.9880 का 2009 (2010 की आपराधिक अपील No.1514)। दिनांक 13/के आदेश द्वारा 8/2010इस अदालत ने मामले को उच्च न्यायालय में भेज दिया और संहिता की धारा 378 (1) और 378 (4) पर विचार करना और पी. एफ. ए. के प्रासंगिक प्रावधान। रिमांड पर, उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और दिनांक 7/1/2011 का आदेश पारित किया।

7. इस पर विचार करने के लिए जो संक्षिप्त बिंदु उत्पन्न होता हैअपील यह है कि क्या किसी शिकायत मामले में, मजिस्ट्रेट को बरी करने के आदेश की अपील सत्र न्यायालय में होगी। संहिता की धारा 378 (1) (ए) के तहत या उच्च न्यायालय के तहत संहिता की धारा 378 (4)।

8. हमारे अनुरोध पर, श्री सिद्धार्थ लूथरा ने अतिरिक्त सीखायाचिकाकर्ता और श्री पी. पी. मल्होत्रा, अतिरिक्त सॉलिसिटर राज्य की ओर से पेश होने वाले जनरल। लिखित प्रस्तुतियाँ है वकील द्वारा दायर किया गया है जिसका हमने सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। श्री.लूथरा ने हमें विधि आयोग की रिपोर्टों के प्रासंगिक अंशों के बारे में बताया। वह हमें संहिता के माध्यम से ले गयादंड प्रक्रिया (संशोधन) विधेयक, 1994 (विधेयक सं. 25/1994)। उन्होंने हमें संहिता की असंशोधित और संशोधित धारा 378 के बारे में भी बताया। प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद, श्री लूथरा ने प्रस्तुत किया कि आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं है सत्र न्यायालय में शिकायत पर शुरू किए गए मामलों में बरी होना। सुश्री लेखी ने भी इसी तरह के तर्क को अपनाया।

9. श्री मल्होत्रा ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के बारे में सीखा एक अलग तर्क को अपनाया और इसलिए, यह है उसकी प्रस्तुतियों को विस्तार से नोट करना आवश्यक है। वकील ने इशारा किया बरी करने के आदेशों के खिलाफ अपील से संबंधित कानून कैसे वर्षों से विकसित हुआ है। वकील ने कहा किदंड प्रक्रिया संहिता, 1861 किसी आदेश के खिलाफ

कोई अपील नहीं दोषमुक्त करने की याचिका दायर की जा सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1872 केवल राज्य सरकार को अपील दायर करने की अनुमति दी गई बरी करने के आदेश के खिलाफ। दंड प्रक्रिया की धारा 417 संहिता, 1898 ने केवल राज्य को इसके खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति दी। बरी करने का आदेश। 1955 में इसे संशोधित किया गया था ताकि अनुमति दी जा सके बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए शिकायतकर्ता। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत, धारा 417 थीधारा 378 द्वारा प्रतिस्थापित। वकील ने बताया कि इसके तहतधारा 378 (4) एक शिकायतकर्ता आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है। दोषमुक्त करने का आदेश। वकील ने तब धारा 378 का उल्लेख किया 2005 के अधिनियम संख्या 25 द्वारा संशोधित संहिता और प्रस्तुत किया कि उप-धारा (1) में एकमात्र परिवर्तन खंड (ए) को जोड़ना है और (ख) उसके लिए। वकील ने इस परिवर्तन को मामूली बताया और प्रस्तुत कियाकि राज्य को बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार है अक्षत रहता है और दूर नहीं किया जाता है। वकील ने भरोसा जताया कि शब्द 'राज्य सरकार, किसी भी मामले में' और प्रस्तुत किया कि ये शब्द राज्य के खिलाफ अपील दायर करने के अधिकार को संरक्षित करते हैं।सभी प्रकार के दोषमुक्ति आदेश। इस अधिकार की कोई सीमा नहीं है। जो भी हो। वकील के अनुसार यह अधिकार संरक्षित है क्योंकि राज्य लोगों का रक्षक है। सुरक्षा और समुदाय की सुरक्षा इसकी चिंता है। भले ही कोई शिकायतकर्ता हो बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील दायर

नहीं करता है, राज्य सरकार इसे जनहित में दायर कर सकती है। वकील भीअपीलों की बहुलता के सवाल पर हमें संबोधित किया। वह मुद्दा हमारे सामने नहीं है। इसलिए, उस का उल्लेख करना, प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। उनकी दलीलों के समर्थन में वकील रखा गयाखेमराज बनाम पर निर्भरता। मध्य प्रदेश राज्य 1, राज्य (दिल्ली प्रशासन) बनाम धरमपास, अकलू अहिर और अन्य बनाम रामदेव राम 3, राज्य बनाम राम बाबू और अन्य 4, खाद्य निरीक्षक बनाम मोइडू 3, प्रसन्नाचारी बनाम चिक्कापिनाचारी & अन्य 6, राज्य महाराष्ट्र बनाम लिम्बाजी सयाजी म्हास्के 7, सरपंच ग्राम पंचायत, पंजाब राज्य और अन्य बनाम जगन नाथ 8 और राज्य उड़ीसा बनाम स्वप्नेश्वर थप्पा9।

10. विवाद को समझने के लिए, यह आवश्यक है कि 2005 के अधिनियम 25 द्वारा इसके संशोधन से पहले संहिता की धारा 378 और उसके द्वारा संशोधित धारा 378 पर एक नज़र।

11. अधिनियम द्वारा इसके संशोधन से पहले संहिता की धारा 378 25/2005 को निम्नानुसार पढ़ा गयाः

"बरी होने की स्थिति में अपील करें।

378. बरी होने की स्थिति में अपील करें। (1) अन्यथा सहेजें उप-धारा (2) में उपबंधित और उपबंधों के अधीनउप-धारा (3) और (5) में राज्य सरकार,किसी भी मामले में, लोक अभियोजक को एक प्रस्तुत करने का निर्देश दें मूल या

अपीलीय आदेश से उच्च न्यायालय में अपीलउच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित बरी करने का 2 [या सत्र न्यायालय द्वारा पारित बरी करने का आदेश पुनरीक्षण में]

(2) यदि किसी भी मामले में बरी करने का ऐसा आदेश पारित किया जाता है।

1. 1976 (1) एससीसी 385।

2. 2001 (10) एससीसी 372।

3. 1973 (2) एससीसी 583।

4. 1970 एडब्ल्यूआर 288।

5. 1988 (2) केएलटी 205।

6. 1959 एआईआर (कांत) 106।

7.1976 (माह.) एलजे 475।

8 1986 (90) पीएलआर 466।

9. 1987 सीआरएल.जे. 612।

दिल्ली के तहत गठित विशेष पुलिस प्रतिष्ठान विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25), या जांच करने के लिए सशक्त किसी अन्य एजेंसी द्वाराइस संहिता के अलावा किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के

तहत किसी अपराध में, केंद्र सरकार जनता को भी निर्देश दे सकती है। उप-धारा (3) के आदेश से उच्च न्यायालय को दोषमुक्त।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा के तहत कोई अपील नहीं (2) उच्च अदालत की छुट्टी के अलावा मनोरंजन किया जाएगा।

(4) यदि किसी भी मामले में है। पर स्थापित और उच्च न्यायालय, एक पर शिकायतकर्ता द्वारा इ बरी करने का ऐसा आदेश पारित किया जाता स ओर से किया गया आवेदन, बरी किए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए विशेष अनुमति देता है शिकायतकर्ता उच्च न्यायालय में ऐसी अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(5) अनुदान के लिए उप-धारा (4) के तहत कोई आवेदन नहींबरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति जहाँ शिकायतकर्ता लोक सेवक है, और प्रत्येक अन्य मामले में साठ दिन, की तारीख से गणना की गईबरी करने का वह आदेश।

(6) यदि किसी भी मामले में, उप-धारा के तहत आवेदन (4) आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने के लिए बरी करने से इनकार कर दिया जाता है, उस आदेश से कोई अपील नहीं की जाती है दोषमुक्ति उप-धारा (1) या उप-धारा (1) के अधीन होगी खंड (2)"।

इस प्रकार, संहिता की पूर्ववर्ती धारा 378 (1) के तहत, राज्यसरकार, किसी भी मामले में, लोक अभियोजक को निर्देश दे सकती है कि एक मूल या से उच्च न्यायालय में एक अपील भेजी204 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2013] 1 एस. सी. आर. के अलावा किसी भी अदालत द्वारा पारित बरी करने का अपीलीय आदेश।उच्च न्यायालय या न्यायालय द्वारा पारित बरी करने का आदेशपुनरीक्षण सत्र। धारा 378 (2) में ऐसे मामले शामिल हैं जहां आदेश दिया गया हो। बरी करने का आदेश किसी भी मामले में पारित किया गया था जिसमें अपराध किया गया थादिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा जाँच की गईदिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत गठित, 1946 या जांच करने के लिए सशक्त किसी अन्य एजेंसी द्वारा संहिता के अलावा किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के तहत किसी अपराध में। में।ऐसे मामलों में केंद्र सरकार जनता को निर्देश भी दे सकती हैअभियोजक एक आदेश से उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करेगा दोषमुक्त करने का। धारा 378 (3) में कहा गया है कि उप के तहत अपील की धारा 378 की धारा (1) और (2) को लागू नहीं किया जा सका। उच्च न्यायालय की अनुमति को छोड़कर मनोरंजन किया गया। उप-खंड (4) संहिता की धारा 378 के तहत बरी करने के आदेश दिए गए हैं। शिकायत पर स्थापित किसी भी मामले में पारित। इसके अनुसार प्रावधान, यदि शिकायतकर्ता द्वारा किए गए आवेदन पर, उच्च न्यायालय आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति देता है दोषमुक्त किए जाने पर, शिकायतकर्ता ऐसी अपील प्रस्तुत कर सकता हैउच्च न्यायालय। संहिता की धारा 378 की उप-धारा (5) में एक सीमा अवधि का प्रावधान किया गया है। धारा की उप-धारा (6) 378 संहिता में कहा गया है कि यदि किसी भी मामले में, आवेदन के तहत उप-धारा (4) से अपील करने के

लिए विशेष अनुमति देने के लिए बरी करने के आदेश को अस्वीकार कर दिया जाता है, उस आदेश से कोई अपील नहीं की जाती है दोषमुक्ति उप-धारा (1) या (2) के तहत होगी। इस प्रकार, यदि उच्च ने अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने से इनकार कर दियशिकायतकर्ता, बरी करने के उस आदेश से कोई अपील नहीं की जा सकती है राज्य या धारा 378 (2) में अनुध्यात अभिकरण द्वारा दाखिल किया गया। इन प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि पहले इसके खिलाफ अपील की गई थी। बरी करने का आदेश केवल उच्च न्यायालय को ही दिया जा सकता है। उपधारा (4) का उद्देश्य दोषमुक्ति के आदेशों को अंतिम रूप देना था।

12. इससे पहले कि हम संशोधित खंड का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ें378 संहिता के, प्रासंगिक खंड को उद्धृत करना आवश्यक है भारत के विधि आयोग की 154 वीं रिपोर्ट में, जिसका नेतृत्व 2005 के अधिनियम 25 द्वारा धारा 378 का संशोधन। वह पढ़ता है इस प्रकारः

"6.12. खंड 37: 205 से बचाव के लिए शक्ति का मनमाना प्रयोग और लापरवाही को कम करना बरी किए जाने पर धारा 378 में संशोधन की मांग की गई है। बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील करना संज्ञेय और गैर-जमानतीय के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय में पुलिस रिपोर्ट पर दर्ज किया गया अपराध जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश के अनुसार। सबके संबंध में पुलिस रिपोर्ट पर दायर अन्य मामले, एक अपील होगी द्वारा पारित बरी करने के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में उच्च

न्यायालय के अलावा कोई अन्य न्यायालय, जिसके द्वारा निर्देश दिया गया हो राज्य सरकार। अपील की सिफारिश करने की शक्ति मजिस्ट्रेट और दूसरी श्रेणी के संबंध में शक्ति राज्य सरकार के साथ जारी रहेगा।

"दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 खंड 37 पर भी यही टिप्पणी है।

13. हालांकि, विधि आयोग की 154 वीं रिपोर्ट ने संकेत दिय कि धारा 378 में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया जा रहा था कि एक अपील इस संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित बरी करने के आदेश के विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट पर दर्ज एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध की अदालत में झूठ बोलेंगे, शब्द "पुलिस रिपोर्ट" संशोधित धारा 378 में शामिल नहीं थे। इस संबंध में, प्रासंगिक उद्धरण का उल्लेख करना आवश्यक हैविधि आयोग की अप्रैल, 2009 की 221 वीं रिपोर्ट। नोट करने के बाद निम्नानुसारः

> "2.9 बरी किए जाने के आदेशों के खिलाफ सभी अपीलें मजिस्ट्रेटों को पहले उच्च न्यायालय में दायर किया जा रहा था 23.06.2006 से प्रभावी, बरी करनेके आदेशों के खिलाफ अपील संज्ञेय और गैर के संबंध में मजिस्ट्रेटों द्वारा पारितपुलिस रिपोर्ट पर दर्ज मामलों में जमानती अपराध किए जा रहे हैं। सत्र न्यायालय में उप-धारा के खंड (ए) के माध्यम से दायर किया गया (1) उक्त खंड से। लेकिन, आदेश के खिलाफ अपील शिकायत पर स्थापित किसी भी

मामले में बरी किया जाना उच्च न्यायालय में दायर किया जाना जारी है, यदि विशेष अनुमति है। उसके द्वारा किए गए आवेदन पर प्रदान किया गया शिकायतकर्ता, उक्त धारा की उप-धारा (4) के माध्यम से।

2.10 धारा 378 को सक्षम करने के दृष्टिकोण से परिवर्तन लों में भी सत्रों में अपील दायर करना न्यायालय, निश्चित रूप से, यह विशेष अवकाश के अनुदान के अधीन"।

विधि आयोग की रिपोर्ट के ये दो उद्धरण यह स्पष्ट है कि हालांकि 'पुलिस रिपोर्ट' शब्दों का उल्लेख नहीं है विधि आयोग ने धारा 378 (1) (ए) में उल्लेख किया है कि संशोधन का प्रभाव यह था कि किसी आदेश के खिलाफ सभी अपीलें एक संज्ञेय के संबंध में एक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित बरी होने का और पुलिस रिपोर्ट पर दर्ज मामलों में गैर-जमानती अपराध हैं सत्र न्यायालय में दायर किया जा रहा है। विधि आयोग ने खेद व्यक्त किया कि इस मामले में अपील दायर करने का कोई प्रावधान नहीं है।के अनुदान के अधीन सत्र न्यायालय में शिकायत मामले इसके लिए विशेष अवकाश लें। इस प्रकार, विधि आयोग ने स्वीकार किया कि संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत अपील की जाएशिकायत के मामले सत्र न्यायालय में दायर किए जा सकते हैं। हम सहमत हैं। इस राय के साथ उन कारणों के लिए जो अब हम बताएँगे।

14. गैर-संशोधित धारा 378 का विश्लेषण करने के बाद यह है -संहिता की धारा 378 पर एक नज़र डालने के लिए आवश्यक है, क्योंकि 2005 के अधिनियम 25 द्वारा संशोधित। यह नीचे लिखा हैः

"378. बरी होने की स्थिति में अपील करें।

[(1) उप-धारा (2) में जैसा अन्यथा प्रदान किया गया है और उसे सहेजें उपधारा (3) और (5) के प्रावधानों के अधीन,"

(क) जिला मजिस्ट्रेट, किसी भी मामले में, निर्देश दे सकता है लोक अभियोजक द्वारा पारित बरी करने के आदेश से सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के लिए संज्ञेय और गैर-जमानतीय के संबंध में मजिस्ट्रेट अपराध;

(ख) राज्य सरकार, किसी भी मामले में, निर्देश दे सकती है लोक अभियोजक उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के लिए सुभाष चंद बनाम मंत्रालय) [रंजना प्रकाश देसाई, जे.] द्वारा पारित दोषमुक्ति के मूल या अपीलीय आदेश से उच्च न्यायालय के अलावा कोई अन्य न्यायालय [जो खंड (ए) के तहत आदेश नहीं है] [या बरी करने का आदेश पारित किया गया पुनरीक्षण में सत्र न्यायालय]

(2) यदि किसी भी मामले में बरी करने का ऐसा आदेश पारित किया जाता है जिसकी दिल्ली द्वारा जाँच की गई

हैदिल्ली के तहत गठित विशेष पुलिस प्रतिष्ठान विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) या जांच करने के लिए सशक्त किसी अन्य एजेंसी द्वारा इसके अलावा किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के तहत अपराध में कोड। केंद्र सरकार, उप-धारा (3) के प्रावधानों के अधीन, जनता को भी निर्देश दे सकती है। अभियोजक एक अपील प्रस्तुत करेगा।

(क) सत्र न्यायालय को, बरी करने के आदेश से एक संज्ञेय के संबंध में एक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित और गैर-जमानती अपराध;

(ख) किसी मूल या अपीलीय आदेश से उच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने का न्यायालय [खंड (क) के तहत आदेश नहीं होने के कारण] या एक आदेश सत्र न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में पारित किया गया।]

(3) [उप-धारा (1) के तहत उच्च न्यायालय में कोई अपील नहीं या छुट्टी के अलावा उप-धारा (2) पर उच्च न्यायालय से विचार किया जाएगा।

(4) यदि किसी भी मामले में बरी करने का ऐसा आदेश पारित किया जाता है। शिकायत और उच्च न्यायालय पर

स्थापित, एक पर शिकायतकर्ता द्वारा इस ओर से किया गया आवेदन, अनुदान, दोषमुक्ति के आदेश से अपील करने के लिए विशेष अनुमति, शिकायतकर्ता उच्च न्यायालय में ऐसी अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(5) उप-धारा (4) के तहत अनुदान के लिए कोई आवेदन नहीं बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति छह की समाप्ति के बाद उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाए महीनों, जहां शिकायतकर्ता एक लोक सेवक है, और प्रत्येक अन्य मामले में साठ दिन, तारीख से गणना की गईबरी करने के उस आदेश का।

(6) यदि किसी भी मामले में, उप-धारा (4) के तहत आवेदन के आदेश से अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने के लिए बरी किए जाने को अस्वीकार कर दिया जाता है, बरी किए जाने के उस आदेश से कोई भी अपील उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत नहीं होगी।"

15. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा के अनुसार 378 (3) धारा 378 (1) (बी) और 378 (2) (बी) के तहत उच्च न्यायालय में दायर किए जाने वाले बरी करने के आदेशों के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय की अनुमति के अलावा संहिता पर विचार नहीं किया जा सकता

है। धारा 378 (1) (ए) में यह प्रावधान है कि, किसी भी मामले में, यदि एक मजिस्ट्रेट के संबंध में बरी करने का आदेश पारित किया जाता है संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध जिला मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। लोक अभियोजक को अदालत में अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दें सत्रों से। उप-धारा 378 की धारा (1) (बी) में प्रावधान है कि किसी भी मामले में राज्य सरकार जनता को निर्देश दे सकती है।मूल से उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के लिए अभियोजकया इसके अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित बरी करने का अपीलीय आदेश उच्च न्यायालय खंड (क) के अधीन आदेश या सत्र न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में पारित बरी करने का आदेश नहीं है।

धारा 378 की उप-धारा (2) बरी करने के आदेशों को संदर्भित करती है। दिल्ली विशेष पुलिस द्वारा जांच किए गए किसी भी मामले में उत्तीर्ण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत या किसी अन्य एजेंसी द्वारा गठित प्रतिष्ठान संहिता के अलावा किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के तहत किसी अपराध की जांच करना। यह प्रावधान उप-धारा (1) के समान है।सिवाय इसके कि यहाँ 'राज्य सरकार' शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया है 'केंद्र सरकार' शब्दों से।

16. यदि हम धारा 378 (1) (ए) और (बी) का विश्लेषण करते हैं, तो यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार लोक अभियोजक को निर्देश नहीं दे सकती है कि संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित

बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करें धारा 378 (1) (बी) द्वारा बनाई गई श्रेणीबद्ध बाधा के कारण।ऐसी अपीलें, जो बरी करने के आदेशों के खिलाफ अपील होती हैं। संज्ञेय और गैर-सुभाष चंद बनाम के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित। (प्रशासन) [रंजन प्रकाश देसाई, जे.]

जमानती अपराध केवल सत्र न्यायालय में दायर किया जा सकता है जिला द्वारा निर्देशित लोक अभियोजक का उदाहरण मजिस्ट्रेट। धारा 378 (1) (बी) "किसी भी मामले में" शब्दों का उपयोग करती है लेकिनकिसी संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित बरी करने के आदेश को छोड़ देता है राज्य सरकार का नियंत्रण। इसलिए, अन्य सभी मामलों मेंजहाँ बरी करने के आदेश पारित किए जाते हैं वहाँ अपील दायर की जा सकती है राज्य सरकार द्वारा निर्देशित लोक अभियोजक को उच्च न्यायालय।

17. धारा 378 की उप-धारा (4) में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं-शिकायत पर स्थापित मामले में बरी किए जाने के आदेश के खिलाफअपील। इसमें कहा गया है कि ऐसे मामले में अगर शिकायतकर्ता उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में आवेदन करता है अपील करने के लिए विशेष अनुमति देता है, शिकायतकर्ता प्रस्तुत कर सकता है उच्च न्यायालय में ऐसी अपील। यह उप-खंड बताता है कि' अन्य से संबंधित उप-धारा (3) के विपरीत 'विशेष अवकाश' बरी किए जाने के आदेश केखिलाफ अपने आप में एक श्रेणी है। शिकायतकर्ता कोई निजी व्यक्ति या

लोक सेवक हो सकता है। यह उप-धारा (5) से स्पष्ट है जो दायर किए गए आवेदन को संदर्भित करता है।शिकायतकर्ता द्वारा विशेष अवकाश के लिए। यह छह महीने का अनुदान देता है। एक शिकायतकर्ता के लिए सीमा की अवधि जो एक लोक सेवक है और प्रत्येक अन्य मामले में आवेदन दाखिल करने के लिए साठ दिन। उप-अनुभाग (6) महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि यदि किसी भी मामले में शिकायतकर्ता उप-धारा (4) के तहत 'विशेष अवकाश' के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है। उप-धारा (1) के तहत बरी करने के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी। या उप-धारा (2) के तहत। इस प्रकार, यदि 'विशेष अवकाश' नहीं दिया जाता हैशिकायतकर्ता को बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिएबात वहीं खत्म होनी चाहिए। न तो जिला मजिस्ट्रेट और न ही राज्य सरकार बरी करने के उस आदेश के खिलाफ अपील कर सकती है। ऐसा प्रतीत होता है कि विचार इस मामले को शांत करने के लिए हैएक स्थिति।

18. चूंकि 'पुलिस रिपोर्ट' शब्दों को हटा दिया गया हैसिफारिश, इस पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है। एक पुलिस रिपोर्ट को संहिता की धारा 2 (आर) के तहत 210 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2013] 1 एस. सी. आर. के रूप में परिभाषित किया गया है एक पुलिस अधिकारी द्वारा उप के तहत मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट संहिता की धारा 173 की धारा (2)। यह एक परिणति है संज्ञेय या गैर-संज्ञेय अपराध की जानकारी प्राप्त करने के बाद पुलिस द्वारा किसी अपराध की जांच। धारा 2 (डी) शिकायत को किसी भी

आरोप के रूप में परिभाषित करती है। मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मौखिक या लिखित रूप से संहिता के तहत, कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है, लेकिन इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है।किए गए को शिकायतकर्ता माना जाएगा। कभी-कभी धारा के तहत किए गए संज्ञेय अपराध की जांच 154 संहिता की समाप्ति एक शिकायत मामले में हो सकती है (मामले) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत)। पी.एफ.ए. अधिनियम के तहत, पी.एफ.ए. की धारा 20 में निर्दिष्ट मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष शिकायत दर्ज करने पर मामले दर्ज किए जाते हैं। पी.एफ.ए. अधिनियम के तहत अधिनियम और अपराध दोनों संज्ञेय हैं और गैर-संज्ञेय। इस प्रकार, क्या कोई मामला एक पर स्थापित मामला है। धारा 378 (4) उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए अदालत। धारा 378 (4) शिकायतकर्ता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है। जहाँ तक राज्य का संबंध है, धारा 378 (1) (बी) के अनुसार, यह किसी भी मामले में, जो कि एक शिकायत पर स्थापित मामले में भी हो सकता है लोक अभियोजक को उच्च न्यायालय में अपील दायर करने का निर्देश दें किसी द्वारा पारित बरी किए जाने के मूल या अपीलीय आदेश से उच्च न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालय। लेकिन जैसा कि हमारे द्वारा कहा गया है इसके ऊपर, एक महत्वपूर्ण अंतर्निर्मित और स्पष्ट प्रतिबंध राज्य की शक्ति। यह लोक अभियोजक को निर्देश नहीं दे सकता है कि एक द्वारा पारित बरी करने के आदेश से अपील प्रस्तुत करेंसंज्ञेय और गैर-संज्ञेय के

संबंध में मजिस्ट्रेटअपराध। ऐसे मामले में जिला मजिस्ट्रेट सुभाष चंद बनाम के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। प्रशासन) [रंजन प्रकाश देसाई, जे.] धारा 378 (1) (ए) लोक अभियोजक को सत्र न्यायालय में अपील दायर करने का निर्देश देती है। यह सही तरीका प्रतीत होता है और संहिता की धारा 378 की सही व्याख्या।

19. श्री मल्होत्रा का कहना सही है कि यह केवल तभी होता है जब दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 417 में 1955 में संशोधन किया गया था कि शिकायतकर्ता को अधिकार दिया गया था अपील दायर करने के लिए उच्च न्यायालय से विशेष अनुमति लें बरी करने के आदेश को चुनौती दें। धारा 417 को प्रतिस्थापित किया गया था 2005 के आई.डी. 1 ने संहिता में एक बड़ा संशोधन किया। इसने धारा 378 (1) (ए) पेश की जिसने जिला मजिस्ट्रेट को, किसी भी मामले में, लोक अभियोजक को निर्देश देने की अनुमति दी - के आदेश से सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत करेंकिसी संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा बरी किया जाना। पहली बार एक प्रावधान था पेश किया गया जिसके तहत बरी करने के आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है। इस तरह की अपीलें थीं संज्ञेय और गैर-जमानती अपराधों में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेशों तक सीमित। धारा 378 (1)(बी) विशेष रूप से और स्पष्ट शब्दों ने इस तरह की अपील दायर करने के राज्य के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार किसी भी मामले

में लोक अभियोजक को उच्च न्यायालय में अपील करने का निर्देश दे सकती है। उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा जिसके अधीन आदेश नहीं है खंड (क) या सत्र न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्त करने का आदेशपुनरीक्षण में। इस प्रकार, राज्य सरकार एक प्रस्तुत नहीं कर सकती है। संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित बरीकरने के आदेश के खिलाफ अपील। हमारे पास है। विधि की 154 वीं रिपोर्ट का खंड 37 पहले से ही उल्लिखित है। भारत का आयोग और दंड संहिता का खंड 37 प्रक्रिया (संशोधन) विधेयक, 1994 जिसमें कहा गया है कि - शक्ति के मनमाने प्रयोग के खिलाफ गार्ड और कम करने के लिएसंज्ञेय और गैर-जमानती अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील प्रदान करना। इस प्रकार, यह कदम विधायिका द्वारा मनमाने ढंग से और [2013] 1 एस.सी.आर. की जांच करने के लिए उठाया गया है। लापरवाही से बरी करना। ऐसा प्रतीत होता है कि वृद्धि के प्रति सचेत रहनाकुछ दोषमुक्तियों के मामले में अप्रमाणित दोषमुक्तियां, विधायिका ने जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश देने में सक्षम बनाया है से थकाऊ और समय लेने वाली प्रक्रिया से बचा जा सके। एक प्रस्ताव के साथ राज्य से संपर्क करना, इसे मंजूरी दिलवाना और फिर अपील दायर करना।

20. यह सच है कि राज्य का इस पर समग्र नियंत्रण है इसके अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्र की कानून और व्यवस्था और सार्वजनिक

व्यवस्था। सभी बरी करने के आदेशों के खिलाफ अपील को प्राथमिकता दे सकते हैं। लेकिन मेजर 2005 के अधिनियम 25 द्वारा धारा 378 में किया गया संशोधन उपेक्षा की गई। इसका एक उद्देश्य है। यह चिंता का विषय नहीं है हवाओं के लिए समुदाय की सुरक्षा। वास्तव में, यह वर्णित कुछ प्रकार के बरी करने के आदेशों के खिलाफ अपील दायर करता है। धारा 378 (1) (ए) में आसान, कम बोझिल और कम समय लेने वाला है। श्री मल्होत्रा द्वारा उद्धृत निर्णय इस प्रकार हैं - दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 417 और 2005 के अधिनियम 25 द्वारा इसके संशोधन से पहले धारा 378 और, इसलिए, वर्तमान मामले से इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।

21. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एक शिकायतकर्ता एक के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए आवेदन दायर कर सकते हैं केवल उच्च न्यायालय को किसी भी प्रकार के दोषमुक्त करने का आदेश। वह नहीं कर सकता। सत्र न्यायालय में ऐसी अपील दायर करें। तत्काल मामले में पी.एफ.ए. अधिनियम की धारा 7 के साथ पढ़ें और नियमों द्वारा दायर किया जाता है शिकायतकर्ता श्री जयसवाल, दिल्ली के माध्यम से स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण प्रशासन। अपीलार्थी को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली द्वारा बरी कर दिया गया था। शिकायतकर्ता एक आवेदन दायर करके बरी होने के आदेश को चुनौती दे सकता है दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए विशेष अनुमति न किमामला संहिता की

धारा 378 (4) द्वारा शासित नहीं है जिसे रद्द कर दिया जाता है। और अलग रख दें। इन परिस्थितियों में अपील की अनुमति है।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी -अमित कुमार शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।